प्रकाशन का 41 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

www.shailsamachar.co.in

शैल समाचार

निष्पक्ष एंव निर्भीक साप्ताहिक

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 41 अंक-27 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 04-11 जुलाई 2016 मूल्य पांच रूपए

आनन्द चौहान और चुन्नी लाल के बाद कुछ और गिरफ्तारीयों की संभावना बढ़ी

शिमला/शैल। वीरभद्र और परिवार के खिलाफ सीबीआई में आय से अधिक संपति और ईडी में चल रहे मनीलॉडरिंग मामलों में चुन्नी लाल और आनन्द चौहान के बाद कुछ आर गिरफ्तारीयां होने की संभावना बढ़ गयी है। क्योंकि जून में आयकर प्राधिकरण के चण्डीगढ़ बैंच में चल रही वीरभद्र सिंह की अपील पर सुनवाई रूक गयी और बैच में कुछ स्थानान्तर हो गये। स्मरणीय हैं कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रहे मामलों में तीनों विभाग-आयकर सीबीआई तथा ईडी आपसी तालमेल बनाये हुए है। आयकर ने अपनी जांच में जो कुछ तथ्य जुटाये हैं उनकी जानकारी यथा स्थिति सीबीआई को दे दी गयी थी। सीबीआई ने अपनी जांच के सारे तथ्य ईडी को उपलब्ध करा दिये। क्योंकि ईडी का आयकर और सीबीआई पर समानान्तर अधिकार क्षेत्र है। इन विभागों में आये मामलों की पूरी जानकारी ईडी को दे दी जाती है।

आनन्द चौहान के बैंक खातों में एकदम करोड़ों रूपया कैश जमा होने और फिर उसे निकाले जाने की जानकारी जब सामान्य रूप से आयकर विभाग में पहुंची थी तब आनन्द चौहान ने आयकर में 22.11.11 को पेश होकर यह बताया था कि उसी का पैसा है और उसका पूरा ब्योरा 15 दिन बाद विभाग को सौंप देगा। लेकिन जब 15 दिन बाद फिर पेश हुआ तो इस पैसे को वीरभद्र के बागीचे की आय बताया और अपने को बागीचे का प्रबन्धक तथा इस आश्य का एक 15.6.08 का हस्ताक्षरित ऐग्रीमेंन्ट भी पेश कर दिया। आनन्द के खाते में करोड़ो जमा हुआ था और उससे वीरभद्र परिवार के सदस्यों के नाम पर करोड़ो की एल आई सी पालिसियां ली गयी थी। जबकि वीरभद्र सिंह ने अपनी आयकर रिटर्नज में तीन साल की कुल आय 47.35 लाख दिखा रखी थी। आनन्द चौहान के ब्यान के बाद वीरभद्र ने मार्च 2012 में इन्ही वर्षो की संशोधित रिटर्न फाईल करके 47.35 की आय को बढकार 6.1 करोड़ दिखा दिया। इस विरोधाभास के कारण पूरे मामले की जांच हुई। जांच में आनन्द चौहान के साथ हुआ एग्रीमैन्ट सही नही पाया गया बल्कि 17.6.08 का इसी बागीचे का एक और एग्रीमैन्ट विश्म्बर दास के साथ मिल गया। इसकी सत्यता भी संदिग्ध हो गयी। बागीचे में करोड़ो के सेब के उत्पादन की संभावनाओं पर बागवानी निदेशालय से रिपोर्ट ली गयी और इस रिपोर्ट ने भी आनन्द चौहान और वीरभद्र के दावों का समर्थन नही किया। यह सेब परवाणु के सेब व्यापारी चुन्नी लाल को बचा दिखवाया गया। इतने सेब की ढुलाई के लिये जो वाहन प्रयुक्त हुए दिखाये गये उन पर ट्रांसपोर्ट निदेशालय से रिपोर्ट ली गयी। इस रिपोर्ट में दिखाये गये नम्बरों के वाहन पाये ही नही गये। सेब की ढुलाई में प्रयुक्त वाहनों की मार्किटिंग बोर्ड के रिकार्ड में एन्ट्री होती है। परन्तु मार्किटिंग बोर्ड की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि ऐसी एन्ट्रीयां उनके रिकार्ड में नही हैं। चुन्नी लाल ने जिन फर्मो से आनन्द चौहान को एक करोड़ की कैश पेमैन्ट एडवासं में उसके सामने उसके कार्यालय में दिया जाना दिखवाया सीबीआई की जांच में वह फर्मे पायी ही नही गयी। इस तरह उत्पादन से लेकर विक्रय तक के सारे दावे सही नही पाये गये हैं। जबकि एलआई सी की रिपोर्ट में 18 पालिसीयां होने की डिटेले दी गयी है। इनमें से कुछ को भुनाकर ग्रेटर कैलाश दिल्ली में खरीदे गये मकान में निवेश किया गया है। इस तरह आनन्द चौहान और चुन्नी लाल के माध्यम से बैंक में आये करोड़ो के प्रत्यक्ष लाभार्थी वीरभद्र और परिवार है यह सीबीआई और ईडी की जांच में आ चुका है।

इसी दौरान वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर के माध्यम से भी छः करोड से अधिक का फ्री लोन वीरभद्र परिवार को मिला है। एक कंपनी में वीरभद्र परिवार के सदस्यों के 90 लाख के शेयर और उनके ओएडी अमित पाल के दस लाख के शेयर सामने आये हैं। वक्कामुल्ला का आय का स्तोत्र भी अभी तक प्रामाणित नही हो पाया है। जबकि इसी दौरान महरौली में फार्म हाऊस की खरीद सामने आ चुकी है। वक्कामुल्ला को लेकर ईडी में अभी तक जांच चल रही है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया में वीरभद्र के ओएसडी को लेकर एक पोस्ट चर्चा में चल रही है। इस पोस्ट मुताबिक अमित पाल ने देश के कई भागों में सात प्लैट और 79 करोड़ के निवेश कर रखे हैं। अमित पाल ने इस पोस्ट के होने की पुष्टि करते हुऐ दावा किया हैं कि सब गल्त है और इसको लेकर उन्होने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा रखी है। जिसे वह शीघ्र ही सार्वजनिक कर देगें। लेकिन पुलिस विभाग ने ऐसी कोई शिकायत आने की पुष्टि नही की है। इस समय अमित पाल को लेकर ऐसी पोस्ट का सामने आना यह इंगित करता है कि यह पोस्ट भी जांच ऐजैन्सीयों की जांच का केन्द्र बनेगी। दूसरी ओर वीरभद्र के प्रधान निजि सुभाष आहलूवालिया के खिलाफ पहले से ही ऊना के दो वकीलों के नाम से एक शिकायत ईडी में लंबित चल रही है। ऐजैन्सी सूत्रों के मुताबिक अमित पाल की पोस्ट और सुभाष की शिकायत पर भी प्रारम्भिक जांच शुरू हो गयी है।

यह भी चर्चा हैं कि सीबीआई ने एक और पुराने मामले को भी नये सिरे से खंगालने का प्रयास शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक चुन्नी लाल और आनन्द चौहान से कांगडा के बड़ा भंगाल को लेकर भी कुछ प्रश्न पूछे गये हैं। ऐजन्सी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां होने की भी संभावना है। स्मरणीय है कि आनन्द चौहान और चुन्नी लाल ने हिमाचल उच्च न्यायालय से वीरभद्र की तर्ज पर राहत मांगी थी जो उन्हे नही मिली है। इस तरह ईडी पर अदालत की ओर से वंदिश नही है। इस मामले में वरिष्ठ वकील आरके आनन्द और सलमान खुर्शीद को शिमला लाकर उनसे राय लिये जाने की भी चर्चा है। कुछ राजनीतिक हल्कों में यह भी चर्चा है कि पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वीरभद्र पद त्यागने का भी फैसला ले सकते हैं।

परिवहन निगम के कर्मचारियों की बर्खास्तगी भारी पड़ सकती है सरकार पर

शिमला/शैल। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रतिबन्ध लगा रखा है। लेकिन यह कर्मचारी इन आदेशों को नज़रअन्दाज करके हड़ताल पर चले गये। उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद हड़ताल पर जाने के लिये इन कर्मचारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला बन गया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों की अनदेखी किये जाने का कड़ा संज्ञान लेते हुये प्रबन्धन को हड़तालियों से सख्ती से निपटने के आदेश जारी कर दिये। उच्च न्यायालय की सख्ती को देखते हुये कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी। लेकिन हड़ताल का नेतृत्व कर रहे तीस कर्मचारी नेताओं ने अन्य कर्मचारियों के साथ हड़ताल समाप्त नहीं की। कर्मचारी नेताओं के इस कदम पर प्रबन्धन ने उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए इन्हे बर्खास्तगी के आदेश थमा दिये।

बर्खास्तगी के आदेश मिलने पर चौबीस कर्मचारी नेताओं ने प्रबन्धन को अपना-अपना शपथ पत्र देकर हड़ताल के लिये क्षमा याचना कर ली। प्रबन्धन की इसी क्षमा याचना पर बोर्ड की बैठक में बर्खास्तगी के आदेश वापिस लेकर इन 24 नेताओं को पुनः सेवा में बहाल कर दिया है। लेकिन इसमें परिवहन मजदूर संघ के अध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर और पांच अन्य कर्मचारी नेताओं ने प्रबन्धन को ना कोई शपथ पत्र दिये न क्षमा याचना की न ही बर्खास्तगी के आदेश की विधिवत अपील दायर की। इसलिये इन छः लोगों की बर्खास्तगी अभी तक बरकरार चल रही है।

हड़ताली नेताओं के खिलाफ उच्च न्यायालय में अवमानना का मामला चल रहा है। अदालत ने शंकर सिंह के जमानती वारंट तक जारी कर दिये हैं। जिन कर्मचारियों ने शपथ पत्र देकर क्षमा याचना की है उन्होंने अपने शपथ पत्रों में इस हड़ताल के शंकर सिंह पर उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया है। हड़ताली कर्मचारियों की बर्खास्तगी के समय इन्हे कोई भी कारण बताओ नोटिस जारी करके इन्हे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया था। अदालत के आदेशों का सहारा लेकर बर्खास्तगी की कारवाई कर दी गई थी। क्या अदालत के आदेशों के नाम पर बिना कारण बताओ नोटिस जारी करके कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा सकता था? क्या अदालत के आदेश की आड में तय प्रक्रिया को नजरअंदाज किया जा सकता था? जिन कर्मचारियो को बर्खास्त कर दिया गया था। क्या उन्हे विधिवत अपील फाईल किये बिना केवल शपथ पत्र पर ही बहाल की किया जा सकता था? भारतीय मंजदूर संघ पर लगाये गये गुमराही के आरोप की क्या जांच नही की जानी चाहिए थी? क्या हड़ताल पर जाने के लिये किसी कर्मचारी को गुमराह किया जा सकता है?

शंकर सिह का ताल्लुक भारतीय मजदूर संघ से है और बीएमएस भाजपा की मजदूर ईकाइ है। इस तरह गुमराही का यह आरोप सीधे भाजपा और आरएसएस पर आ जाता है। इस आरोप पर भाजपा और संघ ने शंकर सिंह को अदालत में यह लडाई लड़ने के लिये हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाने का प्रबन्ध कर दिया है। माना जा रहा है कि शंकर सिह और उसके साथियों ने पिछले केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जे.पी. नड्डा के समाने सारी स्थिति रखी थी जिस पर नड्डा ने उच्च न्यायालय में इस लड़ाई को लड़ने के लिये पूरे प्रबन्ध किये जाने के निर्देश संगठन को दिये हैं। यह भी माना जा रहा है कि इस लड़ाई के माध्यम से भाजपा प्रदेश के कर्मचारियो में अपने संगठन को आगे बढ़ाने का आधार भी जुटा सकती है इसके लिये प्रदेश स्तर पर एक बड़े कर्मचारी आन्दोलन की तैयारी भी की जा रही है।

राज्यपाल स्वच्छता अभियान में हुए शामिल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता विकसित करने पर बल दिया ताकि स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह अभियान सीधे तौर पर पर्यटन विकास से जुड़ा है। पर्यटन गतिविधियों के बढ़ने से आर्थिक समृद्धि के लक्ष्य को अवश्य ही पूरा किया जा सकेगा।

राज्यपाल रेजिडेंट वेल्फेयर सोसायटी न्यू शिमला द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान के अवसर पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने सफाई के प्रति अपने वचनबद्धता को प्रदर्शित करते हुए न्यू शिमला के सेक्टर चार के नजदीक स्वयं, लोगों के साथ सफाई अभियान में भाग लिया। उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सोसायटी की सराहना की तथा कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सोसायटी को महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों में भी भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों को दैनिक दिनचर्या में शामिल किया जाना चाहिए और इसे अन्य क्षेत्रों में भी संचालित किया जाना चाहिए, ताकि अन्यों को भी प्रेरणा मिल सके। उन्होंने कहा कि समाज की भलाई से सम्बन्धित प्रत्येक गतिविधियों में वे शामिल होंगे।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने आस-पास सफाई के प्रति सचेत रहना चाहिए। उन्होंने शिक्षण संस्थानों में प्रभावी ढंग से स्वच्छता अभियान चलाने पर बल दिया। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि महीने में एक बार अपने स्कूल के एक किलोमीटर की परिधि में सफाई अभियान आयोजित करें, ताकि आम लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सकें। उन्होंने कहा कि युवाओं को मुख्यधारा में शामिल होकर राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर भाग लेना चाहिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए सामाजिक अभियानों में सक्रिय योगदान देना चाहिए। उन्होंने युवाओं से मादक द्रव्यों से दूर रहने का भी आहवान किया।

राज्यपाल ने कहा कि पर्यटन राज्य होने के नाते प्रदेश के सभी कस्बों तथा शहरों में स्वच्छता बनाए रखना अति आवश्यक है, ताकि पर्यटकों में प्रदेश की अच्छी छवि बन सके। उन्होंने लोगों, विशेषकर युवाओं से प्रत्येक क्षेत्र में पश्चिमी देशों का अनुसरण न करने को कहा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश भी योग जैसी हमारी अच्छी आदतों को अपना रहे हैं। उन्होंने फास्ट फूड व जंक फूड के स्थान पर जैविक उत्पादों का उपयोग कर अपनी खाने की आदतों में बदलाव लाने की भी सलाह दी।

राज्यपाल ने इस अवसर पर आंतरिक शांति की सुगत यात्रा पर आधारित अशोक चौहान की पुस्तक 'विश्रान्ति' का भी विमोचन किया।

इससे पूर्व, रेजिडेंट वेल्फेयर सोसायटी न्यू शिमला के अध्यक्ष रवि कृष्ण ने राज्यपाल का स्वागत किया और सोसायटी की विभिन्न गतिविधियों बारे जानकारी दी।

डी.ए.वी. स्कूल न्यू शिमला की प्रधानाचार्य अनुराधा शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे।

इसके उपरांत, राज्यपाल ने साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन न्यू शिमला का भी दौरा किया और विद्यार्थियों व लोगों के साथ वार्तालाप किया। उन्होंने साई मंदिर में पूजा अर्चना भी की।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 126 मधावी छात्रों को किया सम्मानित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अमर उजाला द्वारा आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह

उनके लिए गौरव का विषय है कि वे राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सरकारी एवं निजी स्कूलों के दसवीं तथा जमा दो के छात्रों, जिन्होंने इन परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मैरिट हासिल की है, को सम्मानित कर रहे हैं। उन्होंने अमर उजाला समूह की इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करने तथा प्रदेश सरकार के प्रयासों में अपनी सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित कर सहयोग के लिए प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मेधावी छात्रों को पुरस्कार वितरित किए तथा कहा कि मेधावी छात्रों को सम्मानित करना उनके लिए भी गौरव का विषय है।

इस अवसर पर 126 विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए, जिनमें प्रदेश के वे विद्यार्थी भी शामिल हैं, जिन्होंने जे.ई.ई. की परीक्षा में उच्च रैंक प्राप्त किया है।

इससे पूर्व, अमर उजाला के वरिष्ठ कार्यकारी सम्पादक उदय कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने कार्यक्रम के बारे विस्तृत जानकारी दी तथा कहा कि अमर उजाला द्वारा हिमाचल प्रदेश सहित देश के सात अन्य राज्य में वर्ष 2003 से मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान किया।

शिक्षण संस्थानों में स्काउट एवं गाईडज गतिविधियों को दिया जाएगा बढ़ावा: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिक्षा विभाग को प्रदेश के सभी स्कूलों में जहां पर राष्ट्रीय कैडेट कॉरप्स (एनसीसी) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की गतिविधियां संचालित नहीं हो रही हैं, में आने वाले कुछ वर्षों में, प्राथमिकता के आधार पर स्काउट्स एवं गाईडस गतिविधियां आरम्भ करने पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री भारत स्काउट्स एवं गाईडस की राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह गतिविधियां सभी शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य रूप से लागू की जानी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में अनुशासन, देशभक्ति, समुदाय के लिए कार्य करने व आपसी समन्वय की भावना विकसित होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भारत स्काउट्स एवं गाईडस आन्दोलन को बढ़ावा देने के प्रति वचनबद्ध है और दो-तीन वर्षों में इस आन्दोलन के तहत सभी पाठशालाएं लाई जाएंगी, क्योंकि यह विद्यार्थियों को प्रशिक्षण

देने का सबसे बेहतर माध्यम है।

उन्होंने कहा कि स्काउट्स एवं गाईडज आन्दोलन का उद्देश्य युवाओं की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व आध्यात्मिक क्षमताओं को विकसित करना है, ताकि वे एक उत्तरदायी नागरिक बन सके।

वीरभद्र सिंह ने भारत स्काउट्स एवं गाईडज की राज्य इकाई को प्रदान की जाने वाली ग्रांट-इन-ऐड को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की घोषणा की और निर्देश दिए कि कॉर्पस फंड बनाया जाए ताकि धनराशि को विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सके। उन्होंने मण्डी जिला के रिवालसर स्थित स्काउट्स एवं गाईडज के राज्य प्रशिक्षण केन्द्र के कार्य को पूर्ण करने के लिए एक करोड़ रुपये की राशि की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की। इस केन्द्र में प्रदेश सहित अन्य राज्य के युवाओं को भी प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार और धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

उन्होंने शिक्षा विभाग को स्काउट्स एवं गाईडज में अवैतनिक कर्मचारियों की सेवाएं स्काउटिंग उद्देश्य से विभाग में समाहित करने के निर्देश दिए, जिन्होंने आठ वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भारत एवं स्काउट्स गाईडज के प्रदेश चौप्टर की वार्षिक रिपोर्ट को भी जारी किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक- जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार- ऋचा
अन्य सहयोगी
सुशील
रजनीश शर्मा
भारती शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tenders on form No 6&8 for the following works detaile in the table is hereby invited the Executive Engineer ,NH Division HPPWD Pandoh on behalf of Governor of Himachal Pradesh from the eligible contractors of appropriate class registered in HPPWD as per revise enlistment rule so as to reach in his office on 27.7.2016 at 11:00AM. The tenders shall be opened on the same date at 11:30 A.M. in the presence of intending contractors or their authorize representative who wish to be present. The request for issue tenders form along with earnest money must reach in his office up to 3:00 P.M on 25.07.2016 and that tender documents can be had from his office on cash payment noted against each (Non-Refundable) on 26.07.2016 up to 5:00 P.M on any working day. Notice in inviting Tender and other specification and condition of the tender can be seen by the contactor in the office of the Executive Engineer NH Division HPPWD Pandoh during office hour on any working day.

Sr. No. Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	cost of form	Time limit	form No.
1. Restoration of road damages due to laying of O.F.C. by Defense Department on CMM road NH -21 (New NH -03) km 282 /0 310 /0 (SH:-providing Metaling and Tarring on damaged road portion between km 289/0 to 293/0)	1,51,753/-	3,100/-	350/-	One Month	6&8
2. Restoration of road damages due to laying of O.F.C. by Defense Department on CMM road NH -21 (New NH -03) km 257 /0 266 /0 (SH:-providin and Laying G-II, G-III , 20 mm thick premix carpeting and seal coat at various reaches)	1,20,409/-	2,450/-	350/-	One Month	6&8
3. Construction of Diversion for Proposed 4-lane Bridge acroos River Beas km 310/0 at Manali on CMM road NH-21 (New NH-003) against deposit.	4,07, 814/-	8,200/-	350/-	One Month	6&8

TERMS AND CONDITIONS:-The tender documents shall be sold to only those contractors ho fulfill the following terms & conditions as under:

1.The earnest money as shown against the above work in the shape of National Saving Certificate Time Deposit account in any Post office in H.P /FDR of any Scheduled Bank in India duly pledged in the name of Executive Engineer, NH Division HPPWD Pandoh must be accompanied with the application for obtaining tender form Tend application received without earnest money will summarily be rejected .

2. The contractor should possess the following documents (photo copy to be attached with the application for obtaining the tenders documents):

(i) Latest enlistment /renewal of enlistment ordrs
(ii) Proof of valid registration under the HP General Sales Tax Act, 1968.
(iii) Permanent Account number (PAN) issue by the Incomee Tax Department.

3. The contractors should not have more than two work in hand .The detail of executed work /works in hand be supplied at the time of application.

4. The contactor shall have executed similar nature of work at least 40% of the amount put to tender. The work done certificate and details o work in hand should be signed by an officer not below the rank of Executive Engineer. NH Division , HPPWD Pandoh reserves the right to accept or reject the tender without assigning any reason.

Adv. No.-1341/16-17 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

प्रदेश की समृद्धि व विकास में इंजीनियरों की अहम भूमिकाः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि इंजीनियरों के कठिन परिश्रम के बदौलत हिमाचल प्रदेश अपनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद आज अन्य राज्यों के लिए विकास का आदर्श बन कर उभरा है। मुख्यमंत्री जूनियर इंजीनियर एसोसियेशन द्वारा आयोजित 26वीं कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर तथा इलैक्ट्रिकल इंजीनियर लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रदेश को खुशहाल व विकसित करने में अग्रणी रहते हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के गांव को सड़कों और विद्युत व पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का सारा श्रेय प्रदेश के इंजीनियरों को जाता है, जिनकी बदौलत यह सब संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों को सड़क से जोड़ा गया है और प्रत्येक गांव को मोटर योग्य सड़क से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज प्रदेश में 35 हजार किलोमीटर से अधिक लम्बी सड़कें हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के गठन के समय यहां मात्र 288 किलोमीटर सड़कें ही थीं। सभी गांव का विद्युतकरण कर दिया गया है और कुछ की बस्तियां पेयजल सुविधा से वंचित है। यह सब प्रदेश के मेहनतकश इंजीनियरों की बदौलत संभव हुआ है।

उन्होंने कहा कि अधिकतर समय उनके मुख्यमंत्री नेतृत्व काल उनके पास लोक निर्माण, शिक्षा व वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह सभी विभाग प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेशवासियों के सहयोग से तथा कर्मचारियों के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश आदर्श राज्य व सबसे अधिक साक्षर प्रदेश बना है और आज प्रदेश की साक्षरता दर 88 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं की इंजीनियरिंग शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदेश में दो इंजीनियरिंग कॉलेज, ज्यूरी के कोटला में तथा दूसरा नगरोटा बगवां में आरम्भ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इंजीनियरों के बेड़े के अतिरिक्त भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आई.आई.टी.) मण्डी जिले के कमांद में कार्यशील है।

उन्होंने कहा कि अनेक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रदेश में युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में शिक्षा दे रहे हैं और बेरोजगार युवाओं की व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक आईटीआई खोलने की घोषणा की गई है, ताकि युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि गत साढ़े तीन वर्षों के दौरान प्रदेश में 21 आईटीआई खोले गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के साथ हमेशा ही सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं और वे हमेशा ही उनकी समस्याओं के प्रति सचेत रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सभी मामलों को आपसी सौहार्द से सुलझाया गया है।

उन्होंने इस अवसर पर इंजीनियरों को बधाई दी तथा विश्वास जताया कि वे भविष्य में भी इसी उत्साह व समर्पण के साथ कार्य करते रहेंगे।

उन्होंने इस अवसर पर एसोसियेशन द्वारा प्रकाशित स्मारिका का भी विमोचन किया गया तथा एसोसियेशन द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

इससे पूर्व, एसोसियेशन के प्रधान सीता राम ठाकुर तथा पूर्व प्रधान डी.सी. भारद्वाज ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

विधायक संजय रतन और अजय महाजन तथा हिमाचल, पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ के प्रतिनिधियों भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शीघ्र होगा क्रियाशील

शिमला/शैल।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर और पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार और राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) के बीच मंडी जिले के नेर चौक स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के हस्तांतरण के सम्बन्ध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) प्रबोध सक्सेना और ईएसआईसी की ओर से ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक अशोक चंद्र तथा ईएसआईसी के वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त डा. गुंजन गुप्ता ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य संसदीय सचिव नंदलाल और मुख्य सचिव वी.सी. फारका भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

ईएसआईसी कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण पर कुल 924.82 करोड़ रुपये की लागत आई है, और इसे राज्य को 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा कॉलेज आरम्भ होने के दो वर्षों के उपरांत 285.23 करोड़ रुपये की राशि पांच वार्षिक किश्तों में अदा की जाएगी।

कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी।

कॉलेज परिसर में चार खंड, एक पुस्तकालय, पांच मंजिला प्रशासनिक खंड, नर्सिंग कॉलेज व सात संग्रहालय होंगे। अस्पताल में 500 बिस्तरों की सुविधा है और केजुअल्टी वार्ड में 40 बिस्तर, 12 मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर, जिनमें औषधी, इंजेक्शन तथा स्टोर से वार्ड तक के लिए नमूनों की स्व-हस्तांतरण सुविधा के साथ-साथ लेजर प्रणाली से युक्त ऑप्रेशन थियेटर भी होंगे। इसके अतिरिक्त, एक मुख्य ऑपरेशन थियेटर और दो लघु ऑपरेशन थियेटर भी आपातकालीन वार्ड के साथ जोड़े गए हैं।

कॉलेज परिसर में संकाय एवं स्टाफ के लिए 371 आवासों की सुविधा, लड़कों के लिये 300 कमरों का छात्रावास व लड़कियों के लिये 200 कमरों के छात्रावासों की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त, रेजिडेंट चिकित्सक छात्रावास, इंटर्न छात्रावास, नर्सिंग छात्रावास तथा नर्सिंग प्रशिक्षुओं के लिए अलग से आवास बनाए गए हैं। इएसआईसी कॉलेज में रोगियों के लिए एक सराय भवन, एक व्यायामशाला, इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम, एक छोटा शॉपिंग कॉम्पलेक्स तथा एक बड़ी पार्किंग जैसी सुविधाओं का निर्माण किया गया है।

फाइनेंश्यल इंकलूसजन के लिए क्या- क्या कर रही कम्पनी:शिंजिनी

शिमला/शैल। शिंजिनी कुमार, पेटीएमके पेमेंटस बैंक के सीईओ ने शूलिनी विश्वविद्यालय में आयोजित गुरु सिरीज लैक्चर को संबोधित किया। लोक-नीति में स्नातक शिंजिनी कुमार,

16 साल तक भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यरत थी जहां उन्होनें एफडीआई, ट्रेड पेमेंट और फॉरेन बैंकों के संचालन का निरक्षण किया। शिंजिनी, बैंक ऑफ अमरीका मेरिल लिंच में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और प्राइस वाटरहाउस कूपर्स में भी काम कर चुकी हैं।

पेटीएम, भारत की एक जानी मानी ई-कॉमर्स कंपनी है जिसे पिछले साल भारतीय रिजर्व बैंक ने देश का पहला पेमेंटस बैंक शुरू करने का लाइसेंस दिया था। यह बैंक इस साल के अंत तक अपनी सेवाएँ देना शुरू कर देगा।

शिंजिनी कुमार ने छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए अपने निजी जिंदगी से कई बातें साझा की। उन्होनें बताया की वह बिहार के एक छोटे से गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ी। उच्च शिक्षा के लिए उनके गाँव में कोई कॉलेज नहीं था इसलिए माता-पिता ने पटना भेजने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

उनका मानना है कि शैक्षिक संस्थानों और विशेष रूप से शिक्षकों की छात्रों को सार्थक प्रयास करने के लिए प्रेरित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शूलिनी विश्वविद्यालय की तारीफ करते हुए उन्होनें कहा कि शूलिनी विश्वविद्यालय के शिक्षकों के पास यहाँ मौका है कि वह छात्रों को नयी और बेहतर चीजें करने के लिए उनका प्रोत्साहन करें।

मौजूद श्रोताओं को शिंजिनी कुमार ने दो चीजें करने का सुझाव दिया। पहला कि हर व्यक्ति को एक बार अपने देश से बाहर जाना चाहिए और दूसरा अपने देश के गावों के दर्शन। उनके अनुसार यह दोनों चीजे करने से नया परिप्रेक्ष्य और बहुत सी नायाब चीजे सीखने को मिलती हैं।

अपनी टीम के साथ मिलकर शिंजिनी कुमार ने बताया कि कैसे उनकी कंपनी फाइनेंश्यल इंकलूसजन के लिए क्या-क्या प्रयास कर रही है। पेटीएम के पेमेंटस बैंक के बारे में बात करते हुए उन्होनें बताया कि वह एक ऐसा प्रॉडक्ट तैयार करने कि कोशिश कर रहे हैं जो लोगों का फाइनेंस से जुड़ा काम आसान करें और लोग इसे बार बार इस्तेमाल करना पसंद करें। शिंजिनी कुमार का आभार जताते हुए शूलिनी विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रो. पी.के. खोसला ने कहा कि उनके विचार सुनकर निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के छात्रों को भी कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी।

वन एवं मत्स्य मंत्री ने किया मैहला में देवदार का पौधा रोपित कर भू-संरक्षण कार्य शुरू

शिमला/शैल। जर्मन विकास बैंक (के0 एफ0 डब्ल्यू) की सहायता से कांगड़ा- चम्बा जिला के लिए 310 करोड़ रूपए की हिमाचल प्रदेश फोरेस्ट ईको सिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग की परियोजना के अन्तर्गत चम्बा जिला के मैहला में देवदार का पौधा रोपित कर माननीय वन एवं मत्स्य मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने कल रात भू- संरक्षण कार्यों का विधिवत शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर उन्होंने लोगों से आगामी बरसात के मौसम में अधिक से अधिक पौधे लगाकर वनों के विस्तार में सहयोग देने की अपील की। कांगड़ा- चम्बा जिला के आठ वन मण्डलों में छ: वर्षो के लिए चलाई जा रही इस परियोजना के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यो में से भू- कटाव की रोकथाम हेतु वन एवं मत्स्य मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने मैहला खण्ड में ही चैक वाल का पत्थर रखा।

इस मौके पर उपस्थित जिला परिषद् सदस्य अमित भरमौरी व वन विभाग के अधिकारी अवतार सिंह, सी0 पी0डी0 मध्य हिमालयन जलागम परियोजना, डॉ सुरेश कुमार, सी0पी0डी0 (के0 एफ0 डब्ल्यू), डॉ पवनेश कुमार, आर0पी0डी0 मध्य हिमालयन जलागम परियोजना, सी0 बी0 पाण्डे मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) उत्तर तथा डॉ संजीव कुमार वन मण्डल अधिकारी चम्बा ने भी पौधे रोपित किए।

संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है, और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है ....चाणक्य

सम्पादकीय

केन्द्र और केजरीवाल

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का अपने गठन के पहले दिन से लेकर ही मोदी का केन्द्र सरकार से टकराव चल रहा है। केन्द्र सरकार केजरीवाल को अराजकतावादी तक करार दे चुकी है। आम आदमी पार्टी ने भी मोदी सरकार को खुली चुनौती दे रखी है कि वह हटने वाली नहीं है। दोनों सरकारों के बीच चल रहा यह टकराव आज आम आदमी में चर्चा का केन्द्र बन चुका है। यह टकराव मोदी की भाजपा और केजरीवाल की आप पर क्या असर डालेगा यह तो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पायेगा। लेकिन इस टकराव से देश को लाभ होगा यह तय है। क्योंकि इस समय देश एक राजनीतिक बदलाव के दौर में गुजर रहा है। देश में व्यवस्था के खिलाफ पहली बार स्व. जय प्रकाश नारायण की समग्रक्रान्ति से जो स्वर उभरे थे उन्हे आज एक स्पष्ट दिशा–दशा मिलने के संकेत झलकते नजर आ रहे हैं। यहां तक पहुंचने के लिये देश ने जनता पार्टी के टूटने से लेकर स्व. वी.पी.सिंह की भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली लड़ाई उसके बाद मण्डल बनाम कमंडल और फिर रामदेव तथा अन्ना आन्दोलन का एक लम्बा दौर देखा है। इसमें किसकी क्या भूमिका रही है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह रहा है कि हर बार कांग्रेस के समस्त विकल्प की तलाश मुख्य बिन्दु रहा है। क्योंकि बहुभाषी और बहुधर्मी देश की संस्कृति ने वाम विचारधारा तथा आर एस एस की हिन्दु अवधारणा को कभी विकल्प के रूप में नहीं स्वीकारा है। यदि ऐसा होता तो वाम दल केरल, बंगाल और त्रिपुरा से निकलकर केन्द्र तक में स्वीकार्य हो चुके होते। संघ भी 1967 में पहली बार जन संघ को सबिंद्ध सरकारों में कुछ राज्यों में मिली भागीदारी के बाद राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता बना चुका होता।

केजरीवाल और मोदी के टकराव को इस बड़े परिप्रेक्ष में देखना होगा। मोदी और भाजपा का मूल आधार संघ है। संघ अपने गठन से लेकर आज तक हिन्दु अवधारणा पर टिका हुआ है। हिन्दु अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिये समान नागरिक संहिता, धारा 370 और राम मन्दिर निर्माण जैसे मुद्दे इसका मुख्य आधार रहें हैं। आज केन्द्र में 282 सीटें जीतकर संघ का आर्थिक चिन्तन भी भामाशाही अवधारणा पर टिका है। इसके लिये उसे अदानी–अंबानी जैसे भामाशाह पोषित करना भी अनिवार्यता है। संघ–भाजपा को अपने हिन्दु ऐजैण्डे को आगे बढ़ाने में कांग्रेस और वामदलों से कोई चुनौती नहीं है। क्योंकि कांग्रेस को भ्रष्टाचारी छवि के आरोपों से बाहर निकलने में बहुत वक्त लगेगा। वामदल भी बंगाल खोने के बाद बचाव की मुद्रा में चल रहे हैं। ऐसे में केवल केजरीवाल की आप ही रह जाती है जिससे मोदी–भाजपा को खतरा हो सकता है।

भाजपा को केजरीवाल से खतरा क्यों है? इस सवाल को समझने के लिये थोड़ा सा अन्ना आन्दोलन को समझना होगा। अन्ना आन्दोलन संघ का प्रायोजित ऐजैण्डा था यह स्पष्ट हो चुका है। केजरीवाल और आप भी इसी आन्दोलन का प्रतिफल है। आज संयोगवंश केजरीवाल और अन्ना के रास्ते अलग हो चुके हैं। केजरीवाल तो आप बनाकर भाजपा–कांग्रेस का विकल्प बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन अन्ना अपने आन्दोलन का फिर से आह्वान कर पाने की स्थिति में नहीं है। केजरीवाल पहले कभी राजनीतिक सत्ता में नही रहे हैं और आज भी अपने पास कोई विभाग न रखकर सत्ता के विकेन्द्रीकरण के ऐजैण्डे को मूर्त रूप दे दिया है। आज केजरीवाल और मोदी सरकार में दिल्ली सरकार के अधिकारों की व्याख्या और सीमा ही टकराव का केन्द्र बिन्दु है। इस मुद्दे को लेकर आप सरकार सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच चुकी है और सर्वोच्च में दो न्यायधीश इस इस मुद्दे की सुनवाई से बिना कारण बताये पीछे हट गये हैं। इससे अधिकारों के इस मामले में ठोस आधार का होना स्पष्ट होता है। इस परिदृश्य में केजरीवाल और आप का पक्ष जायज नज़र आता है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर केजरीवाल की स्वीकार्यता बनती नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस–भाजपा और वामदलों को छोड़कर बाकी दल अपने हर आयोजन में केजरीवाल को आमन्त्रित करने लग गये हैं। ऐसे में केजरीवाल को भी कुछ मामलों में विशेष सावधानी से चलना होगा। उनके राजनीतिक और प्रशासनिक सहयोगीयों पर लगने वाले भ्रष्टाचार के हर आरोप पर पूरी सावधानी से कदम उठाने होगें। क्योंकि जब उनके पहले कानून मंत्री पर आरोप लगे थे तब शुरू में उन्होंने उसका बचाव किया लेकिन जैसे ही पूरे तथ्यों की जानकारी मिली तो अपना स्टैण्ड बदला और जनता को स्पष्ट बताया भी। आज उनके प्रधान सविच की गिरफ्तारी के मामले में भी देश उनसे वैसी ही स्पष्टता की उम्मीद रखता है। इसी के साथ आगे संगठन को बढ़ाने के लिये जहां भी इकाई गठित की जायेगी वहां पदाधिकारियो का चयन करते समय पर्याप्त सावधानियां बरतनी होंगी।

स्वरोजगार के लिये 10 लाख तक ऋण सुविधा

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनएलआरएम) का उद्देश्य सभी गरीब परिवारों तक पहुंचना और सम्मानजनक एवं बेहतर जीवन यापन करने के लिय गरीबी से उभरने तक इनका पोषण करना है। हिमाचल प्रदेश में इस कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्य में बीपीएल एवं गरीब परिवारों से लगभग 50 हजार महिलाओं को 9146 स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से मिशन की मुख्यधारा में सम्मिलित किया गया है।

❖ एनआरएलएम के कार्यान्वयन में अग्रणी बनकर उभरा हिमाचल

❖ महिला सशक्तिकरण का संबल बना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

वर्ष 2013 – 14 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यान्वयन के उपरांत से विगत लगभग तीन वर्षों में प्रदेश में लगभग 11 हजार स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है जिन्हें 90 करोड़ रुपये की लाभ प्रदान किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 300 महिलाओं की सुदृढ़ मानव संसाधन का भी विकास किया गया है। विगत वर्षों के दौरान 52 ग्राम संगठनों का गठन किया गया है तथा उन्होंने सामुदायिक निवेश निधि के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त किया है। मिशन

का उद्देश्य इस वित्तीय वर्ष के दौरान समस्त हिमाचल में अपनी गतिविधियों को फैलाना है ताकि प्रदेश के प्रत्येक जिले में महिलाओं की स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विकास में सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित बनाया जा सके।

मिशन का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये उन्हें बार–बार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। गरीबी उन्मूलन के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये गरीब परिवारों की महिलाओं में सामाजिक संचेतना, संस्थागत और क्षमता निर्माण, वित्तीय समावेशन, संतृप्ति दृष्टिकोण, कौशल उन्नयन और सतत् आजीविका का सृजन करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रदेश में एनएलआरएम प्रथम अप्रैल, 2013 से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रथम चरण में यह कार्यक्रम राज्य के पांच विकास खण्डों क्रमशः कण्डाघाट, मण्डी सदर, नूरपुर, हरोली और बसन्तपुर में कार्यान्वित किया जा रहा है। शेष बचे विकास खण्डों में यह कार्यक्रम अगले चार वर्षो के दौरान प्रभावी तौर पर लागू किया जाएगा।

प्रदेश के लिये केन्द्र सरकार ने कार्यक्रम आरम्भ होने से आज तक कुल 1492.11 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की है जिसमें से 333 लाख रूपये राज्य सरकार ने अपने हिस्सेदारी के तौर पर वहन किए है।

प्रदेश में एनआरएलएम के अन्तर्गत आरम्भ में बीपीएल परिवारों की महिलाओं को सम्मिलित किया गया और बाद में अति गरीब एवं आंशिक तौर पर गरीब परिवारों की महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इन समूहों में 70 प्रतिशत महिलाएं बीपीएल परिवारों से हैं जबकि 30 प्रतिशत मार्जनली गरीब परिवारों से शामिल की गई हैं। ग्रामीण स्तर पर इन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए गये हैं। स्वंय सहायता समूह में कम से कम 5 महिलाएं होना अनिवार्य है। 10 से 20 स्वयं सहायता समूहों के ग्राम संगठन बनाए गए हैं जबकि इतने ही ग्राम संगठनों की कलस्टर लेवल फेडरेशन बनाई गई हैं। प्रदेश में 16199 स्वंय सहायता समूहों का चयन करके इन्हें एमआईएस पोर्टल डाटा बेस में अपलोड किया गया है।

स्वयं सहायता समूहों को आजीविका अर्जित करने एवं किसी भी प्रकार के व्यवसाय करने के लिये इन्हें बैंकों से सम्बद्ध करके सात प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह को इसके सृजन के छः माह के पश्चात् विभाग द्वारा रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया जा रहा है। रिवॉल्विंग फंड तथा निजी बचत को मार्जिन मनी मानकर बैंक द्वारा प्रत्येक समूह को 2 से 3 लाख रूपये तक ऋण प्रदान कर रहा है। स्वंय सहायता समूह की उपलब्धियों के आधार पर यह ऋण बार–बार प्रदान किया जाता है और एक समूह को अधिकतम 10 लाख रूपये तक ऋण प्रदान किया जा सकता है। इसके लिये बैंको की उप समिति का गठन किया गया है।

प्रदेश में अभी तक 6345 स्वंय सहायता समूहों को विभिन्न बैंको से सम्बद्ध करके 59.09 करोड़ रूपये के ऋण उपलब्ध करवाए गए हैं। इन समूहों को 2.97 करोड़ रूपये रिवॉल्विंग फंड के रूप में विभाग द्वारा वितरित किये गए हैं।

ऋण लेने वाली महिलाओं के समूह द्वारा एक वर्ष के भीतर ऋण की अदायगी करने पर ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है, इस तरह महिलाओं को केवल चार प्रतिशत ब्याज ही देना पड़ेगा। इस राशि को विभाग स्वंय वहन कर रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपना कारोबार अच्छा चलने पर अन्य महिला जो स्वयं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हो, को ऋण प्रदान कर सकती हैं। ऐसा करने से महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने की सुविधा मिली है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वंय सहायता समूहों के संस्थानीकरण एवं क्षमता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। हि.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यान्वयन विकास खण्डों में गहन तरीके से कार्य किया जाएगा। गहन ब्लॉक के सभी सक्रिय महिला स्वंय सहायता समूहों के सदस्यों की पहचान की जाएगी ताकि वे स्वंय सहायता समूहों एवं ग्राम संगठन को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिये आंतरिक सामुदायिक संसाधान व्यक्ति (सीआरपी) की जिम्मेदारी लेने के लिये सक्षम हों।

कार्यक्रम के तहत प्रथम दो वित्त वर्षो के दौरान प्रदेश में स्वंय सहायता समूहों का गठन एवं उन्हें बैंको से सम्बद्ध करवाने पर विशेष बल प्रदान किया गया। अब चूंकि मिशन की मूल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिये चालू वित्त वर्ष के दौरान मानव संसाधन सृजन के लिये मुख्य फोकस सामाजिक लामबंदी, संस्था एवं सामुदायिक निर्माण पर होगा। सक्रिय महिलाओं को आंतरिक सामुदायिक संसाधन के तौर पर विकसित किया जायेगा ताकि वे विभाग एवं बैंको पर निर्भर न रहकर सतत् आजीविका अर्जित करके पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकें।

डूबे ऋणों के बोझ तले डूबते बैंक

प्रकाश कारात

बैंकों का डूबे ऋणों का बोझ पिछले छः महीने में और बढ़ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजातरीन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है। इस रिपोर्ट के अनुसार सकल डूबे हुए ऋणों (नॉन परफार्मिंग एसेट्स एनपीए) का अनुपात, जो पिछले सितंबर में 5.1 फीसद पर था, इस साल मार्च में तेजी से बढकर 7.6 फीसद पर पहुंच गया। इसमें इतना और जोड़ लें कि तमाम डूबे हुए ऋणों में बड़े ऋण लेने वालो का हिस्सा बढकर 86.4 फीसद पर पहुंच चुका है, जबकि 2016 के मार्च तक कुल ऋणों में बड़े ऋण लेने वालों का हिस्सा 58 फीसद ही था। एक अनुमान के अनुसार, भुगतान विफलता के खतरे में माने जा रहे कार्पोरेट ऋणों का आंकड़ा 6.7 लाख करोड़ रुपए का है।

डूबे हुए ऋणों या बैंकों के नॉन परफार्मिग एसेट्स की समस्या तब उभरकर सामने आ गयी, जब रिजर्व बैंक ने बैंकों से मांग की कि वे अपनी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता की समीक्षा करें तथा अपनी बैलेंस शीट्स में स्वच्छता लाएं। इस कसरत के फलस्वरूप पता चला कि बैंकों के डूबे हुए ऋण, जितने बताए जा रहे थे उससे कहीं बहुत ज्यादा हैं। बैंकिंग क्षेत्र की यह दुर्दशा यूपीए-द्वितीय की सरकार द्वारा अब मोदी सरकार द्वारा नवउदारवादी बलाघात को बढ़ाए जाने के चलते हुई है, जिसके तहत बैंकों पर खासतौर पर ढांचागत क्षेत्र में निजी कंपनियों को बहुत उदारता से ऋण देने के लिए दबाव डाला जा रहा था। चूंकि सरकार ने राजकोषीय जिम्मेदारी की बेडियां अपनी पांवों में डाल रखी थीं, ढांचागत परियोजनाओं में निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) के नाम पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बिजली उत्पादन, बिजली वितरण, बंदरगाह, राजमार्ग जैसे ढांचागत क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा ऋण देने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था।

इन हालात में दरबारी पूंजीवाद को बढ़ावा दिए जाने ने यह सुनिश्चित किया कि कृपाप्राप्त बड़े कार्पोरेट खिलाडियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अंधाधुंध तरीके से ऋण दें। निजी निवेश संचालित ढांचागत विकास की विफलता अब खुलकर सामने आ गयी है। एस्सार, जेपी, जीएमआर, रिलायंस एडीएजी, अडानी, लेंको आदि बड़ी ढांचागत कंपनियों पर डूबे हुए ऋणों का भारी बोझ, इसी का सबूत है।

लेकिन, बैंकों के डूबे हुए ऋणों के संकट का सरकार ने तोड़ यह निकाला कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पक्के डिफॉल्टरों के ऋणों को अपने खातों से ही निकाल दें। इस तरह, 2013 से 2015 के बीच बैंकों ने पूरे 1.24 लाख करोड़ रुपए के ऋण बट्टे खाते में डाले थे। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जान-बूझकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण मारने वालों पर 2015 के दिसंबर तक बैंकों का 66,190 करोड़ रुपया बकाया था। चौतरफा दबाव में रिजर्व बैंक ने हाल ही में ऐसे जान-बूझकर बैंकों का ऋण मारने वालों के नाम सार्वजनिक करने का फैसला लिया है। लेकिन, असली मुद्दा तो यह है कि ऐसे जान-बूझकर कर्जा मारने वालों के खिलाफ, उनकी परिसंपत्तियों के सरकारी अधिग्रहण तथा उनकी परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिए, दबाए गए पैसे की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। अब तक तो सिर्फ इतना हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति, कंपनी आदि को जान-बूझकर कर्जा न चुकाने वाला घोषित कर दिया जाता है, उसके लिए आइंदा ऋण के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और उसे किसी भी बैंक या संस्था से कोई भी अतिरिक्त ऋण सुविधा हासिल नहीं हो सकती है। सरकार तथा रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश देने चाहिए कि बड़े कार्पोरेट, जिन पर बैंकों का सबसे ज्यादा ऋण होता है, एक समुचित समय सीमा में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋण लौटाएं।

इन डूबे हुए ऋणों के चलते बैंकों को जो राजस्व हानि होती है, उसका बोझ खुदरा ऋण क्षेत्र पर अतिरिक्त बोझ बनाकर डाल दिया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि बड़े ऋण मारने वालों की करनी की सजा आवास, शिक्षा आदि के लिए छोटे-छोटे ऋण लेने वालों को और छोटे उद्यमों को भुगतनी पड़ती है।

नवउदारवादी निजाम में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा पकड़ी गयी पूरी दिशा की ही समीक्षा किए जाने की जरूरत है। सच्चाई यह है कि आज ज्यादातर कृषि ऋण, किसानों को न मिलकर, कृषि-बिजनेस तथा गैर-कृषि कामों में ही जाते हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए ऋण वितरण की पूरी व्यवस्था को ही भीतर से ध्वस्त कर दिया गया है। मोदी सरकार निजीकरण को नये सिरे से गति देने में लगी हुई है।

बैंकिंग क्षेत्र के निजीकरण को आगे बढ़ाए जाने से हालात और बदतर ही होंगे। रिजर्व बैंक का यह फैसला पूरी तरह से गलत है कि निजी बैंकों के लिए लाइसेंस दिए जाएं, जिसमें कार्पोरेटों द्वारा प्रायोजित निजी बैंक भी शामिल हैं। एक ओर तो सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने के लिए बहुत कम आवंटन किया है और दूसरी ओर सरकार का यह रुख है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों के विनिवेश के जरिए पूंजी जुटायी जाए। इन दोनों कदमों का योग, सार्वजनिक बैंकिंग व्यवस्था के निजीकरण की ओर ही ले जाएगा।

जरूरत इस बात की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पर्याप्त पूंजी डालने की व्यवस्था की जाए। सरकार ने 2019 तक 700 अरब डालर की पूंजी सहायता दिलाने का जो वादा किया है, अपर्याप्त है। सार्वजनिक बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की संशोधित योजना को लागू करते हुए सरकार को नवउदारवादी राजकोषीय चिंताओं को परे खिसका देना चाहिए। यह भी जरूरी है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए उदार होकर ऋण देने के निर्देश देना बंद करे। इस तरह का वित्त जुटाने के लिए एक वैकल्पिक संस्थागत तंत्र होना चाहिए।

साभार www.deshbandhu.co.in से

देश के 91 प्रमुख जलाशयों की संग्रहण स्थिति

06 जुलाई, 2016 को समाप्त सप्ताह के दौरान देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 28.208 बीसीएम (अरब घन मीटर) जल का संग्रहण आंका गया। यह इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 18 प्रतिशत है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के कुल संग्रहण का 55 प्रतिशत तथा पिछले दस वर्षों के औसत जल संग्रहण का 74 प्रतिशत है।

इन 91 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 157.799 बीसीएम है, जो देश की अनुमानित कुल जल संग्रहण क्षमता 253.388 बीसीएम का लगभग 62 प्रतिशत है। इन 91 जलाशयों में से 37 जलाशय ऐसे हैं जो 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ पनबिजली संबंधी लाभ देते हैं।

उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान आते हैं। इस क्षेत्र में 18.01 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले छह जलाशय हैं, जो केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 4.77 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 27 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 44 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 34 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कमतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी कमतर है।

पूर्वी क्षेत्र में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा आते हैं। इस क्षेत्र में 18.83 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 15 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 3.50 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 19 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 29 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 19 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कमतर है, लेकिन यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण के बराबर है।

पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात तथा महाराष्ट्र आते हैं। इस क्षेत्र में 27.07 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 27 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 3.16 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 12 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 26 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 26 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कमतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से कमतर है।

मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आते हैं। इस क्षेत्र में 42.30 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 12 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 9.22 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 22 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 31 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 17 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कमतर है, लेकिन यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहेऔसत संग्रहण से भी बेहतर है।

दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश , तेलंगाना (दोनों राज्यों में दो संयुक्त परियोजना), कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु आते हैं। इस क्षेत्र में 51.59 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 31 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 7.55 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 15 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 35 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 28 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कमतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी कमतर है।

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण की स्थिति बेहतर है उनमें राजस्थान, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण कमतर है उनमें हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश तेलंगाना (दोनों राज्यों में दो संयुक्त परियोजनाएं), पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक शामिल हैं।

पसूका

हिमाचल पर्यटन: विकास की आवश्यकता

शिमला/शैल। भारतवर्ष का पर्यटन उद्योग प्रतिवर्ष लगभग 1500 करोड़ अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा के अर्जन के साथ ही लगभग 1.5 करोड़ लोगों की रोजी-रोटी का साधन है। विदेशी मेहमानों के लिए हमारे देश में पर्यटन के हर रंग विद्यमान हैं। एक समृद्ध इतिहास की गाथा गाते प्राचीन से प्राचीनतम हमारे दुर्ग, ऐतिहासिक धरोहरें, अति रोचक पुरातात्विक महत्त्व की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतियां, साम्प्रदायिक सोहार्द का वातावरण, विभिन्न रंगों में रंगे उत्सव और त्यौहार, अगणित प्रकार की पारम्परिक वेशभूषाएं, नाना प्रकार के व्यंजन, मुम्बई जैसे अत्याधुनिक शहर से लेकर समाज की मुख्यधारा से नितान्त विरक्त आदिवासी प्रजातियाँ, सैकड़ों किलोमीटरों में फैले रेगिस्तान, वन्यजीवों से सुशोभित राष्ट्रीय उद्यान, कल कल करती हजारों मीलों लम्बी नदियाँ, विशाल झरने, महासागरों के अति सुन्दर किनारे, विशाल मन्दिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरूद्वारे, बौद्ध मोनेस्ट्री, साल भर बर्फ से ढकी पर्वतीय क्षेत्रों की गगनचुंबी चोटियाँ, विशाल हिमखण्ड, हिमनद, पर्वतों के रोचक टेड़े-मेढ़े रास्ते, रमणीक हृदयंगम प्राकृतिक दृश्य और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी 'अतिथि देवो भवः' की संस्कृति। आखिर क्या नहीं है हमारे भारत में, एक पर्यटक को आकर्षित करने के लिए।

हिमालय पर्वत में बसे हिमाचल प्रदेश की बात कुछ और ही है। शीतल जलवायु, प्रदूषण रहित, शान्त, सुरक्षित वातावरण एवं सरल जनमानस के कारण हिमाचल आज भारतवर्ष के अव्वल नम्बर के पर्यटन स्थलों में से एक है। ईश्वर ने हमें दिल खोलकर प्राकृतिक सौन्दर्य का उपहार प्रदान किया है। 60 से 80 के दशक का एक समय वह था जब भारत की सारा की सारा फिल्म उद्योग अपने चलचित्रें में रमणीक दृश्य शामिल करने के लिए हिमाचल और कश्मीर जैसे पर्वतीय प्रदेशों की ओर रूख करता था और दूर दराज के प्राकृतिक सौन्दर्य को अपने कैमरों में कैद करता था। पर्यटन विकास में फिल्म उद्योग का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। संभवतः इसी से प्रेरित होकर पर्यटकों ने हिमाचल और कश्मीर जैसे पर्वतीय राज्यों की ओर रूख किया। आज ग्लोबल वार्मिंग और बदलती जलवायु के कारण भी ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों के पर्यटक पर्वतीय क्षेत्रों की ओर रूख करते हैं। हिमाचल पर्यटन आज चरम पर है। वर्ष 2014 में प्रदेश में कुल 1 करोड़ 63 लाख पर्यटक से अधिक पहुंचे। वर्ष 2016 की समाप्ति तक इस आंकड़े का 2 करोड़ तक छूने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में पर्यटन और परिवहन के लिए अनुमानित राजस्व व्यय रू. 1752 करोड़ है, जो कि कुल अनुमानित राजस्व व्यय का 6.55% है। 'हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम' का प्रदेश के कुल राजकोष में 10% प्रतिवर्ष का योगदान होता है। प्रदेश में लाखों व्यक्ति प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिससे प्रदेश में करोड़ों रूपयों की आय होती है। पर्यटन व्यवसाय दिन दोगुनी-रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। मगर चिन्ता का विषय है कि हिमाचल के गठन के 45 वर्षों में कई सरकारें आयी और गई, मगर अनुपातिक रूप पर्यटन अविकसित ही रहा। आज भी यहाँ पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। प्रकृति प्रदत्त उपहार को सहेजेने में हम लगभग विफल रहे हैं। पर्यटक एक बार आने के पश्चात् दोबारा आने के पहले कई बार सोचते हैं। आखिर ऐसा क्यों? पर्यटन की स्थिति भविष्य में यथावत बनी रहे, इसके लिए कुछ कठोर कदम उठाने आवश्यक हो गए हैं

हिमाचल का नाम 'हिम' अर्थात बर्फ पर आधारित है। मगर बढ़ते शहरीकरण के कारण बर्फबारी वर्ष-दर-वर्ष घट रही है, जो चिन्ता का विषय है। बर्फ ही नहीं रहेगी तो हिमाचल के नाम का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। वैध-अवैध निर्माण पर अंकुश लगाकर वर्ष-दर-वर्ष बढते तापमान और घटती बर्फबारी पर नियंत्रण किया जाये, तभी पर्यटन का भविष्य सुरक्षित माना जा सकता है।

पर्यटक यहाँ की मनमोहक हरियाली से सर्वाधिक प्रभावित है। प्रयास इस बात के लिए किये जाएँ कि यहाँ की हरियाली नष्ट न होने पाए और वातावरण में शुद्धता बनी रहे। हम वैध-अवैध निर्माण और विकास के नाम पर प्राकृतिक वातावरण नष्ट कर रहे हैं और कंकरीट के जंगल खड़े कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार एक पेड़ वर्षभर में 650 पोंड ऑक्सीजन देता है, जो दो व्यक्तियों को वर्षभर के लिए पर्याप्त होती है। शिमला-कालका फोरलेन के लिए 25000 पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलायी जा रही है। साथ ही शिमला-मनाली फोरलेन का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। साथ ही बहुत सारे राजमार्गो की घोषणा करके सरकारें अपनी पीठ थपथपा रही हैं। लेकिन अन्जाम क्या होगा? कंकरीट के जंगल खड़े करने के बजाय हरियाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अन्यथा 100 वर्षो बाद पर्यटकों को फोटो खींचने के लिए भी पेड़ एवं हरियाली ढूँढनी पड़ेगी।

यूनेस्को विश्व हेरिटेज कालका-शिमला रेलवे की स्थिति ब्रिटिश काल से लगभग वही है। वही पुराने स्टेशन, वही सुरंगें और वही पुल। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी कोई प्रचार प्रसार नहीं, इसीलिए उनको इसका ज्यादा ज्ञान भी नहीं है। फोरलेन और राजमार्गों में हम बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, जिनको बनाने के लिए जंगल के जंगल और साफ किये जा रहे हैं। रेलवे एवं हवाई अड्डों को विकसित किया जाये तो निश्चित रूप से पर्यटकों को कुछ नया मिलेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी यह उचित होगा।

नित्य हजारों की संख्या में निजी वाहन प्रदेश में पहुँच रहे हैं। जिनको शिमला जैसे बड़े स्थलों में पार्किंग की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पर्यटक वाहनों को सुविधा देने के बजाय सरकार 'नो-पार्किंग' का चालान काटकर यातायात व्यवस्था सुधार रही है और अपना जेब भर रही है, जो कि सर्वथा अनुचित है। इससे पर्यटकों की मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अगर सडकों पर अवैध अतिक्रमण सम्पूर्ण रूप हटा दिया जाये तो वाहनों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सकता है और पार्किंग की समस्या संपूर्ण रूप से हल हो सकती है।

अनगिनत वाहनों की संख्या को नियंत्रित कर, पर्यटन विभाग की ओर से दो या तीन दिन के पैकज के हिसाब से सार्वजनिक परिवहन जैसे बसें व टैक्सी उपलब्ध करवानी चाहिए। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या भी नियंत्रित होगी साथ ही पर्यटन भी किफायती होगा।

पुराने और उबाऊ पड़ चुके पर्यटन स्थलों के अलावा भी दूर दराज के क्षेत्रों में नए स्थान जैसे बाग-बगीचे, चिल्ड्रनस पार्क, वाटर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग मार्ग, हरे-भरे रिसॉर्ट्स, फोटोग्राफी साइट्स, प्राचीन धरोहर आदि को विकसित जायें तो पर्यटकों को कुछ नया आकर्षण मिलेगा और वो बार-बार आने को लालायित रहेगा

हिमालय की गोद में बसे होने के कारण प्रदेश में 'जीओ-टूरिज्म' अर्थात 'भू-पर्यटन' की अपार संभावनाएँ बनती हैं। इस पर कुछ प्रयास भी हुए पर सिरे न चढ़ सके। 'भू-पर्यटन' लिए ऐसे स्थान चयनित करने होते हैं, जो भू-वैज्ञानिक और भौगोलिक दृष्टि से आकर्षक हों। जैसे चूनापत्थर की प्राकृतिक गुफाएं एवं उनमे पाई जाने वाली स्टेलेकटाईट एवं स्टेलेगमाईट स्थालाकृतियाँ, प्राकृतिक सन्तुलन बनाती विशाल चट्टानें, प्राकृतिक सुरंगें, धरती से फूटते झरने आदि। ऐसे स्थान यदि पर्यटन के लिए विकसित किया जाये तो निश्चित की यह पर्यटकों के एक विशेष वर्ग के लिए अति रोचक प्रतीत होंगे।

पर्यटन के लिए एक ऐसा स्वस्थ वातावरण तैयार हो कि पर्यटक को ग्राहक की दृष्टि से न देखकर अतिथि के रूप में देखा जाये।

ईश्वर के प्राकृतिक सौन्दर्य रुपी इस उपहार को अगर हम समय रहते नहीं सहेज पाए तो दूरगामी परिणाम अत्यंत भयानक होंगे। समय के साथ अगर हिमाचल पर्यटन को विकसित न किया गया तो हिमाचल भी प्रदूषण, अतिक्रमण, गर्मी, सूखा, अनावृष्टि आदि का शिकार हो जायेगा एवं पर्यटक यहाँ से मुंह मोड़ने लगेगा। जिसका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ के पर्यटन व्यवसाय आर्थिक व्यवस्था पर निश्चत रूप से पड़ेगा।

-डा. महेश कुमार वर्मा-
प्रबंधक, NMDC Limited, शिमला

गवर्नर व मुख्यमंत्री से जेपी कंपनी व अंबुजा में अधिग्रहित जमीनों में SC के फैसले को लागू करवाने की मांग

शिमला/शैल। स्वैच्छिक संस्था मांगल विकास परिषद, मांगल ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मांग की

है कि जिला सोलन के बागा व भलग में जेपी कंपनी के लिए अधिग्रहित की गई 200 बीघा से ज्याादा व दाड़ला में अंबुजा सीमेंट कंपनी के लिए अधिग्रहित 100 बीघा के करीब जमीन के अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के मुताबिक रदद माना जाए। उन्होंने मांग कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पालना करने को लेकर सरकारी मशीनरी को जरूरी कार्यवाही करने के आदेश दें। परिषद ने कहा कि जे पी कंपनी व अंबुजा ही नहीं इस फैसले को पूरे प्रदेश में लागू किया जाए।

परिषद के महासचिव व हाईकोर्ट के एडवोकेट नंद लाल चौहान ने 'द वर्किंग फ्रैंडस कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य' और रतन सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्यूटजेशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट -2013 से पहले जिन किसानों की जमीनें का जबरन अधिग्रहण हो चुका है व पांच व पांच साल से ज्यादा किसानों के कब्जे में हैं, उस जमीन की अधिग्रहण प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करार दे दिया है।

चौहान ने कहा कि जे पी कंपनी के लिए आठ साल व अंबुजा कंपनी के लिए 12 साल पहले जमीनें अधिग्रहित की गई थी। किसान इन खेती योग्य जमीनों को कंपनी के लिए नहीं देना चाहते थे। लेकिन सरकार ने कंपनी के लिए जबरन अधिग्रहण कर दिया और मुआवजा ट्रेजरी में जमा करा दिया। लेकिन इन किसानों ने विरोध स्वरूप अपनी जमीनों का ये मुआवजा नहीं लिया और जमीन अपने कब्जे में ही रखी। इन जमीनों में किसान आज भी खेती कर रहे हैं। जबकि सरकार ने इन कंपनियों के दबाव व मिलीभगत से सरकारी दस्तावेजों में किसानों की सहमति के बिना इन जमीनों का इंतकाल कंपनियों के नाम कर दिया। जबकि असल में कब्जा इन्हीं किसानों के पास है।

चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी स्थिति में की गई अधिग्रहण प्रक्रिया को अवैध माना है। इसलिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरे प्रदेश में लागू करना चाहिए ताकि किसानों को तकलीफों का सामना न करना पड़े।

चौहान ने कहा कि इस फैसले के लागू न होने की सूरत में किसानों को इन जमीनों पर न तो किसान क्रेडिट कार्ड पर बैंकों से कर्ज मिल रहा हैं और न ही ग्रीन हाउस, पानी के टैंकों व किसानों के लिए मिलने वाली बाकी सब्सिडी इन किसानों को मिल पा रही है।

जिससे इन किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा हैं व किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से भी वचिंत रहना पड़ रहा है।

जेबीटी अध्यापकों के 600, अनुबंध आधार पर पीजीटी के 500 पद भरने को स्वीकृति

❖ हि.प्र. पट्टा नियम 2014 में संशोधन को मंजूरी
❖ सेब प्रापण के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना 2016 स्वीकृत
❖ 37 नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति

शिमला। मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 2013 में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया गया तथा इसमें शिमला तथा कांगड़ा जिले में विस्थापित व्यक्ति मुआवजा व पुनर्स्थापन अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अनुरूप गैर कानूनी तरीके से बेची गई पट्टा सम्पत्तियों को शामिल किया गया है। मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की।

अधिकतर विस्थापित सम्पत्ति का उपयोग लम्बे समय से किया जा रहा है, में कानूनी कार्यवाही से बचने का निर्णय लिया गया था और वर्तमान में पट्टा नियम 2013 के कुछ नियमों की जांच कर आवश्यक संशोधन किया जाए। यह नियम केवल उन सम्पत्तियों पर लागू होगें जो गैर कानूनी तरीके से बेची गई है।

मंत्रिमण्डल ने मंडी मध्यस्थता योजना 2016 के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत लगभग 1.11 मीट्रिक टन सेब का प्रापण 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से करने के अतिरिक्त 2 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम हैंडलिंग चार्जिज तथा 3 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम बिक्री अनुमान के रूप में निर्धारित किए गए हैं।

योजना के तहत फल उत्पादक क्षेत्रों में मांग के आधार पर 279 प्रापण केन्द्र खोले जाएंगे, जिसमें से 162 एकत्रिकरण केन्द्र एचपीएमसी द्वारा खोले व क्रियाशील किए जाएंगे तथा 117 हिमफैड द्वारा संचालित किए जाएंगे। यह योजना प्रदेश में 20 जुलाई से 31 अक्तूबर, 2016 तक कार्यान्वित की जाएगी।

लगभग 1400 रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे

मंत्रिमण्डल ने प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर जेबीटी अध्यापकों के 600 पद भरने को स्वीकृति।

शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर स्नातकोत्तर अध्यापकों (पीजीटी) के 500 पदों को भरने को स्वीकृति।

आबकारी एवं कराधान विभाग में नियमित आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 108 पद भरने को स्वीकृति।

कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां में नए राजकीय फार्मेसी कॉलेज में विभिन्न श्रेणियों के 30 पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति।

पर्यटन विभाग में 29 पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति।

उद्योग विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से माइनिंग गार्डो के 26 पदों को भरने की स्वीकृति।

मंत्रिमण्डल ने पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 19 पदों को भरने को स्वीकृति।

लोक निर्माण विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (बागवानी) के 8 पद भरने को स्वीकृति।

आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों के 7 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर भरने की स्वीकृति।

एच.पी.एम.सी. में अनुबंध आधार पर चालक के दो पद भरने को स्वीकृति।

सोलन जिले के नौणी स्थित डॉ. वाई.एस. परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय में तकनीकी सहायक श्रेणी-1 के एक पद भरने को स्वीकृति।

उद्योग विभाग में अनुबंध आधार पर प्रोग्रामर प्रथम श्रेणी (राजपत्रित) के एक पद के सृजन व भरने को स्वीकृति।

एचपीएमसी में कम्पनी सचिव के एक पद के सृजन को स्वीकृति।

युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के एक पद को अनुबंध आधार पर सृजन व भरने को स्वीकृति।

निदेशक भू-रिकार्ड शिमला में दैनिक दिहाड़ी के आधार पर चालक का एक पद भरने को स्वीकृति।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करते हुए मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में 37 नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्दों को स्टॉफ सहित खोलने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल की कांगड़ा जिले के ज्वाली तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुठलैहड़ को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्वीकृति।

बैठक में सोलन जिला के चमियाण में आवश्यक स्टॉफ सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) को स्वीकृति।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप सिरमौर जिला के पावंटा साहिब में 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित करने को स्वीकृति।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के सुघ-भटोली स्थित निजी तौर पर चलाए जा रहे दीन दयाल महेश डिग्री कॉलेज में विभिन्न श्रेणियों के 28 पदों के सृजन व भरने की अनुमति के साथ सरकार के अधीन करने को अनुमति प्रदान की।

कांगड़ा जिले के शिवनगर स्थित स्वामी विवेकानंद ग्रामोदय कॉलेज को कॉलेज के सेवारत शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ सरकारी नियंत्रण में लेने का निर्णय।

सिरमौर जिला के राजगढ़ स्थित राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय।

बैठक में केन्द्रीय विद्यालय संगठन को मण्डी जिला के संधोल स्थित केन्द्रीय विद्यालय को क्रियाशील करने के लिए पट्टे पर भूमि देने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री वर्दी योजना के अन्तर्गत जमा एक व जमा दो के विद्यार्थियों को स्कूली वर्दी प्रदान करने का निर्णय लिया।

धर्मशाला स्थित नगर निगम के महापौर के सरकारी वाहन पर एंबर बिकॉन लाईट लगाने का निर्णय।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के विभिन्न भागों में नए स्वीकृत 16 पशु औषधालय में आवश्यक स्टाफ सहित खोलने को स्वीकृति।

यह भी निर्णय लिया गया कि 13 पशु औषधालयों को आवश्यक स्टाफ सहित पशु अस्पताल में स्तरोन्नत किया जाए।

मंत्रिमण्डल ने राजकीय आईटीआई मनाली स्थित पतली कूहल में हियर एंड स्किन केयर ट्रेड को बदल कर इलैक्ट्रिशयन ट्रेड की स्वीकृति।

बिहार के बोध गया में सराय भवन का निर्माण करने के लिए धनराशि प्रदान करने को स्वीकृति।

मंत्रिमण्डल ने राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के निदेशकों की नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्तो के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।

विभिन्न सरकारी विभागों को पदों को भरने में बेवजह होने वाली देरी से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को हर वर्ष 28 फरवरी व 30 जून तक पदों को भरने के लिए मांग पत्र पहुंच जाने चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि आयोग के परामर्श से तिथियों को पहले भी किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश नगर एवं नियोजन नियम, 2014 के संधोशन को स्वीकृति।

हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबन्धन उत्तरदायित्व अधिनियम, 2014 के नियमों को बनाने की मंजूरी।

हिमाचल प्रदेश मूल्यवर्द्धक कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कर अधिसूचियों में संशोधन को स्वीकृति।

एस.एल.एस.डब्ल्यू.सी. एवं एम.ए. द्वारा 20 नए औद्योगिक प्रस्ताव को मंजूरी

♦ 543.26 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित
♦ 1100 लोगों को मिलेगा रोजगार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में यहां राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण (एस.एल.एस. डब्ल्यू.सी. एवं एम.ए.) की 79वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें लगभग 543. 26 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश के 20 नए औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने तथा वर्तमान इकाइयों के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई, इन इकाइयों में लगभग 1100 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होगे।

उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मुख्य सचिव वी.सी. फारका और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

बैठक में जिन नए प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई उनमें मैसर्ज सागर बायोटैक को एग्रो-बायोटैक उद्योग परियोजना/समेकित टिशू कल्चर प्रयोगशाला स्थापित करने, मैसर्ज तायशा एग्रो उद्योग को कल्टिवेटर ब्लेड, रोटावेटर ब्लेड इत्यादि के निर्माण, मैसर्ज हरसोरिया हेल्थकेयर को आई.वी. केनूला व अन्य भाग तथा एवीएफ, कैथेटर तथा टी.पी. स्थापित करने की मंजूरी शामिल हैं।

विस्तार व विविधिकरण तथा संशोधित प्रस्ताव मे मैसर्ज जे.बी. रोलिंग इकाई दो को औद्योगिक एमएस इंगोटस और बिलेटस (इंडक्शन फरनेस) के साथ कॉनकास्ट, को स्थापित करने, मैसर्ज नवरन एडवांसड नेनो-प्रोडक्स डिवेल्पमेंट इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड को नेनो जिंक ऑक्साइड व नेनो

मेगनिशियम हाईड्रोक्लोराइड निर्माण के लिए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने, मैसर्ज डॉ. रेड्डीज प्रयोगशालाएं लिमिटेड इकाई-1 में दवा सूत्रीकरण के निर्माण के लिए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने, मैसर्ज ब्रूक्स लेबोट्रीज लिमिटेड को इंजेक्शन, ड्राई सिरप, टेबलेटस के निर्माण, मैसर्ज मॉनडेलज इंडिया फूडज प्राईवेट लिमिटेड (इकाई-दो) (जो पूर्व में मैसर्ज कैडबरी इंडिया लिमिटेड, इकाई-दो) फाईव स्टार चॉकलेट, जैम्स और अन्य चॉकलेट तैयार करने, मैसर्ज अब्बॉट हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड को फेंसिडल, एसगायपरिन और हाइमसेल तैयार करने, मैसर्ज बेट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड प्लास्टिक लेमिनेटड ट्यूब, प्लास्टिक लेमिनेटड एल्यूमिनियम फॉयलस की प्रिंटिंग तथा मैसर्ज आईडल स्ट्रिप्स को पैट बोतल एचडीपीई बोतल के ढक्कन के निर्माण के लिए मंजूरी शामिल है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

स्कैंडल की गप–शप

वीरभद्र सातवीं बार?

शिमला/शैल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुक्खु ने एक साक्षातकार में कहा है कि पार्टी प्रदेश में अगला चुनाव सामूहिक नेतृत्व के तहत लड़ेगी। उन्होने यह भी कहा है कि वीरभद्र एक बड़ा चेहरा हैं। लेकिन पार्टी के अन्दर और भी बड़े चेहरे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और पंजाब की प्रभारी डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने कहा है कि वीरभद्र सातवीं बार प्रदेश के मुख्य मन्त्री बनेगें। प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ मंत्री विद्या स्टोक्स तो बहुत अरसे से वीरभद्र को प्रदेश का अगला मुख्यमन्त्री घोषित कर चुकी है। कांग्रेस के इन नेताओं के ब्यानों में कितना दम है यह तो समय ही बतायेगा। लेकिन वीरभद्र अभी तक मुख्यमत्री पद पर आसीन है यह हकीकत आशा कुमारी, राकेश कालिया, राजेश धर्माणी, जी एस बाली और ठाकुर कौल सिंह जैसे नेता जो एक समय वीरभद्र के विरोधीयों में गिने जाते थे आज यह सब अपने–अपने कारणों से खामोश होकर बैठे चुके हैं। सबकी नजरें सीबीआई और ईडी की जांच रिपोर्टों पर अदालत में पेश होने वाले चालानों के परिणामों पर टिकी हुई हैं। यह स्पष्ट है कि देर सवेर यह मामले अदालत में पहुंचकर वीरभद्र परिवार के लिये कठिनाई पेश करेंगे ही। लेकिन यह भविष्य का सवाल है। इसमें कितना वक्त लगेगा। यह भी निश्चित रूप से नही कहा जा सकता। लेकिन इस सबका परिणाम सामने है कि अब वीरभद्र की वकालत में भी मुखर होकर ज्यादा स्वर सामने नही आ रहे हैं।

चुनाव अगले वर्ष दिसम्बर में होने हैं लेकिन जिस ढंग से वीरभद्र प्रदेश का तूफानी दौरा कर रहे हैं और बजटीय संसाधनों की परवाह किये बिना जनता में घोषणाएं करते चले जा रहें है उससे समय पूर्व चुनावों की संभावना के भी पूरे संकेत उभर रहे हैं। वीरभद्र के दौरों के कारण ही वीरभद्र के मन्त्री और विधायक भी अपने–अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार अभियान में ही जूट गये हैं जैसे–जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाएं क्षीण होती जा रही है। ऐसी स्थिति बन गयी है जिसमें यह लग रहा है कि कांग्रेस को अगले चुनावों तक वीरभद्र का नेतृत्व झेलना पड़ेगा।

नड्डा के दौरे ने बदले प्रदेश के सियासी समीकरण

शिमला/शैल। केन्द्रिय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी.नड्डा के हिमाचल के दो दौरों ने प्रदेश के सियासी समीकरणों को हिल्लाकर रख दिया है। पहले दौरे में उन्होने कुल्लू में प्रदेश की सियासत में वापसि का संकेत जिस अदांज में दिया था इस दौरे में उस अंदाज को पीटरहॉफ में ऐसे मुखर किया जिससे यह स्पष्ट संकेत उभरा कि भाजपा हाईकमान ने उन्हे प्रदेश का नेतृत्व सौंपने का मूक ऐलान कर दिया है। गडकरी के नड्डा को लिखे पत्र को ऐसे प्रचारित प्रसारित किया गया जैसे की इन नैशनल हाइवेज़ की अधिसूचना वास्तव में ही केन्द्र ने जारी कर दी हो। जबकि इन नैशनल हाइवेज़ को अमली शक्ल मिल भी पायेगी या नही यह सन्देह भी स्वयं गडकरी के पत्र से ही झलकता है। नड्डा और भाजपा के इस अन्दाज का असर पार्टी और चुनावों पर क्या पड़ेगा यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा लेकिन वीरभद्र और उनकी सरकार पूरी खामोशी बरतने से सियासी समीकरणों में बदलाव अश्वय आया है।

हालांकि नड्डा के नाम का किसी ने कहीं कोई एलान नहीं किया लेकिन राजधानी के एक नामी सरकारी होटल पीटरहाफ में नड्डा ने जिस तरह से प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार और मोदी सरकार में सड़क मंत्री गडकरी के मंत्रालय के नेशनल हाइवे के अधिकारियों के साथ फर्राटा बैठक की व अपने मंत्रालय के नहीं गडकरी के मंत्रालय में दखल देकर अधिकारियों की क्लास ली है, वो सब कुछ साफ साफ बयां कर गई हैं।

इसके अलावा नड्डा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ एक भी बोल नहीं बोला। यहां तक सरकार के कामकाज पर भी मौन साधा गए। जबकि प्रदेश भाजपा व धूमल खेमा पिछले तीन सालों से वीरभद्र सिंह पर ताबड़तोड़ हमले करता आया है। वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार पर न तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलते है और न ही उनके मंत्री जेपी नड्डा कोई हमला बोलते हैं। जबकि मोदी सरकार की सीबीआई वीरभद्र सिंह के खिलाफ जांच कर रही हैं। यहां ये महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व जगत प्रकाश नड्डा दोनों के ही वीरभद्र सिंह से दोस्ताना रिश्ते हैं। दूसरे वीरभद्र सिंह की ये मजबूरी है कि प्रदेश में धूमल नहीं कोई और नेता भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा बने।

उधर दूसरी ओर प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी केंद्रीय मंत्री ने दूसरे मंत्री के मंत्रालय के कामकाजों का जायजा लिया हो। गडकरी व नड्डा के आपस में याराना रिश्ते है। शायद ये लिबर्टी गडकरी की ओर से इसी याराना की वजह से मिली हो।

इसके अलावा पीटरहाफ में भाजपा नेताओं की फौज जिस तरह से खड़ी हुई वो अपने आप में चौंकाने वाली थी। उनके स्वागत में बैंड बाजा भी बजा तो फूल–मालाएं पहनाने को भी भाजपा नेता आतुर रहे। भाजपा अध्यक्ष सतपाल सती से लेकर धूमल खेमे के विरोधी मंडी जिला से विधायक महेंद्र सिंह ठाकुर, जयराम ठाकुर, शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज, अर्की के विधायक गोबिंद शर्मा नड्डा के चारों ओर घूमते रहे।

इसके अलावा धूमल खेमा भी पीछे नहीं था। जिला कुल्लू से गोबिंद ठाकुर, जिला सिरमौर (पहले सोलन) राजीव बिंदल उनके आसपास रहे। इसके अलावा भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा व बीरेंद्र कश्यप भी इस मौके पर मौजूद रहे लेकिन जलवा सिर्फ नडडा का ही रहा। राजीव बिंदल मीडिया को काबू में रखने का काम करते रहे चूंकि नड्डा मीडिया से बात करने में तय समय से देरी से आ रहे थे। सो बिंदल पूरी तरह से चौकस रहे।

नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने दो सालों में 60 नेशनल हाइवे हिमाचल को दिए है जिन पर कम से कम 13 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें से 56 नेशनल हाईवे तो इसी साल मंजूर किए गए हैं। इन हाईवे पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के अफसरों से उनकी बैठक हुई है व उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए है कि वो एक सप्ताह के भीतर इन हाइवे में होने वाले किसी भी तरह के बदलाव की रिपोर्ट मोदी सरकार को भेज दें ताकि इन पर काम हो सके। नड्डा ने कहा कि जैसे ही बदलाव की रिपोर्ट मोदी सरकार के पास पहुंचेगी उसी के साथ डीपीआर तैयार करने के लिए कंस्लटेंट नियुक्त करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि वो चाहते है कि प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो।

वीरभद्र सिंह सरकार पर हमला करने से बचते हुए नडडा ने केवल इतना कहा कि जिस रफ्तार में मोदी सरकार काम कर रही है वीरभद्र सिंह सरकार भी उसी रफ्तार में काम करें। वीरभद्र सिंह सरकार की रफ्तार तेज नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनावों में वो भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे इसका उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वो बोले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केबिनेट में बाखुबी काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो विकास के मसले पर बात करने आए है। दिलचस्प ये रहा कि वो वीरभद्र सिंह व उनके सरकार के कामकाज पर किसी भी तरह का हमला करने से बार –बार बचते रहे। उन्होंने उन पर सीधा हमला नहीं किया।

यहां ये महत्वपूर्ण है कि अगर नड्डा को हिमाचल से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर उतारा जाता है तो फिर धूमल परिवार की राजनीति पर विराम लगना तय है। आगामी चुनावों में प्रदेश में पिता पुत्रों की सरकार एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। ये भाजपा आलाकमान भी जानता है। कांग्रेस में वीरभद्र सिंह व विक्रमादित्य सता पर काबिज है तो भाजपा पर धूमल व अनुराग का कब्जा है।

आज दिलचस्प स्थिति भाजपा अध्यक्ष सतपाल सती की रही है। वो नड्डा खेमे की ओर भी है और धूमल खेमे की ओर भी। हालांकि वो अपना झुकाव किस ओर रखेंगे ये आगामी दिनों में तय हो जाएगा। समझा जा रह है एबीवीपी का खेमा नड्डा की ओर झुकेगा। एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश कुमार भी बिलासपुर से हैं। बताते है कि वो राज्यसभा जाने का सपना पाले हैं। नड्डा उनके लिए सीढ़ी बन सकते है। इन सबकों को एक दूसरे की जरूरत है। हालांकि भाजपा के लिए धूमल को नजरअंदाज करना आसान नहीं हैं। लेकिन कहते है कि उनके लिए गवर्नरी का पद रखा हुआ है जबकि उनके पुत्र अनुराग ठाकुर के लिए हमीरपुर लोकसभा सीट सुरक्षित है। ऐसे में नड्डा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से पिता–पुत्र की सरकार की काट भी मिल जाएगी। अब देखना ये है कि भाजपा आगे क्या करती है।

हड़ताली मजदूरों के मामले में सिंघा के पत्र से सरकार की नीयत व नीति सवालों में

शिमला/शैल। जिला किन्नौर के 450 मेगावाट के शोंगटोंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट में मजदूरों की अपनी मांगों को लेकर चल रही हड़ताल के 112 वें दिन वामपंथी नेता राकेश सिंघा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम खुला पत्र लिख कर खुलासा किया कि इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे ठेकेदारों ने अपने रूख के चलते एसपी का तबादला डेढ़ महीने के भीतर करवा दिया था। सिंघा ने दावा किया कि ऐसा इसलिए किया क्योंकि उक्त एसपी ने हड़ताली मजदूरों पर लाठीचार्ज करने से इंकार कर दिया था।

शोंगटोंग में 950 के करीब मजदूर पिछले साढ़े तीन महीनों से हड़ताल पर है व आश्चर्यजनक तौर पर प्रोजेक्ट पर जो भी काम चल रहा है वो पुलिस पहरे में चल रहा है। इतने दिनों तक पुलिस को मजदूरों से भिड़ाना सरकारी खजाने व प्रदेश के मानव संसाधनों से खिलवाड़ करने जैसा है। किन्नौर में पिछले साढ़े तीन महीनों से पुलिस बटालियन के अलावा जिले की पुलिस गार्द मजदूरों को काबू करने पर लगा रखी। हालांकि प्रदेश के उद्योगमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व सीएम खुद हर जगह डंका पीटते आ रहे हैं कि प्रदेश का माहौल बेहद शांतिपूर्ण है व निवेशकों को न्यौता भेजते रहते है। लेकिन निवेशक पिछले साढ़े तीन महीने से ये सब समझबूझ रहे है कि किस तरह से शोंगटोंग हाइड्ल प्रोजेक्ट में पुलिस पहरे में काम हो रहा है।

ये चौंकाने वाला हैं कि आखिर वो कौन–कौन ताकतें हैं जो मजदूरों की हड़ताल समाप्त नहीं कराना चाहती हैं। अंगुली मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह खेमे के नेताओं की ओर से उठाई जा रही है। इस तरह के इल्जाम वामपंथी नेता सरेआम लगा चुके है। जबकि जिला किन्नौर में तैनात अफसर भी दबी जुबान में ये कहने लगे है। अगर ये सच है तो ये सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल है।

हालांकि संवेदनशील सरकार को अब तक कोई हल निकाल लेना चाहिए था। लेकिन कोई समाधान न निकलने पर वामपंथी नेता सिंघा ने सरकार की संवेदनशीलता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है।

यहीं नहीं डीसी किन्नौर नरेश कुमार लठ्ठ को प्रदेश हाईकोर्ट ने हड़ताली मजदूरो व प्रोजेक्ट प्रबंधन से बातचीत कर कोई समझौता कराने का निर्देश दिया था लेकिन अभी तक कोई वार्ता शुरू नहीं हुई है। ऐसे में माकपा व किसान सभा ने लठ के खिलाफ कारवाई करने की मांग कर दी है। वामपंथी सचिवालय के बाहर भी धरना दे रहे हैं। इसके अलावा डीसी आफिस के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे है। विरोध प्रदर्शन न भी होत हुये भी सरकार को ये मसला सुलझाना चाहिए था। चूंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी व्यक्ति उसकी सीमा के भीतर काम कर रहा हो उसके वाजिब अधिकारों की रक्षा हो। लेकिन धीरे धीरे ये लगने लगा है कि सरकार में या सरकार के करीब कोई ऐसे है जिन्हें विवाद न सुलझने से बड़ा मुनाफा हो रहा हैं।

ऐसे में सिंघा ने मुख्यमंत्री के रोहडू में ठेकेदारों पर बरसने के एक दिन बाद उन्हें पत्र लिख कहा हैं कि शोंगटोंग में भी ठेकेदार भी नेता, अफसर ऐसा ही खेल खेल रहे है।

सिंघा की सीएम वीरभद्र सिंह को खुली चिट्ठी

Dated : 06.7.2016

My Dear Virbhadra Singh Ji,

You are aware of the industrial dispute going on in Shongtong-Karcham Hydel Project today, is the 112 day of the strike and the 5th day of indefinite fast. Inspite of this, efforts are not visible to provide justice to the workers.

There is a huge hoarding close to the secretariat building belonging to the public relations deptt, which reads " MANNIYE MUKHYAMANTRI SH. VIRBHADRA SINGH JI KE KUSHAL NETRITWA MEIN SAMVEDANSHEEL SARKAR- SWACHH PRASHASAN".

I do not understand what a sensitive govt means, but by all democratic and humane yardsticks the attitude of the government. Towards the Shongtong-Karcham hydel project workers cannot be covered within the parameter of sensitivity.

The workers are firm to carryon the struggle. It is a reaction to the exploitation by the company and the contractors. In the past who ever demanded the implementation of law was terminated from service.

In October, 2013, the President Jeet Negi, the Gen. Secretary Rajvansh Negi, the Vice President Kuldip Negi were terminated from service along with three other activists of the union.

Soam Dev Negi was one amongst the three. Their only crime was to demand, payment of minimum wages, over time wages, weekly off, wage slip as per law, provident fund deductions, accommodation as per law etc.

Sonam Negi one of the terminated workers was tortured and humiliated by the contractors. Being unable to digest the pain he was going threw, chose to commit suicide by jumping into the Satluj River on 18.11.2013. This is recorded in the Police daily diaries of police station Recong Peo vide G.D entry No: 32(A). His body was subsequently recovered in a decomposed state on 28.4.2014.

The contractors eclipsed the sensitivity of the Govt. and under their pressure the case did not proceed. The truth has not been revealed. There were contractors were able to transfer S.P Kinnaur only within one and half months of his joining. What was his crime? He did not lath charge the peaceful striking workers.

The labour officer has been transferred his crime was that he recorded that pending the conciliation proceedings the Patel Management and contractors could neither recruit or terminate the services of the workers as per the provisions of the Law.

I am no one to advise the govt. But if the slogan of sensitivity is to prevail. It must be practiced by the govt. The Rights of the workers must be given to them. Justice must be done with the family Soam Dev Negi which includes his wife and two school going children. This is another test case for your govt, whether it sensitive to the problems o f the people. Slogans must not be given for slogan sake. They must be practiced.

With Regards

Rakesh Singha